दैनिक जागरण

प्रार्थना वास्तव में आत्मा की पुकार होती है

कश्मीर में शांति

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना महत्वपूर्ण है कि कश्मीर समस्या का समाधान होगा और यह कैसे होगा, इसे सरकार अच्छी तरह जानती है। चूंकि उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में काम हो रहा है इसलिए ऐसा होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसका एक कारण यह भी है कि पिछले कुछ समय से कश्मीर के हालात अपेक्षाकृत काबू में दिख रहे हैं। वहां बचे-खुचे आतंकियों का सफाया हो रहा है, अलगाववादियों एवं पाकिस्तानपरस्त तत्वों के हौसले पस्त हैं और पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ में भी कमी दिख रही है। इस सबके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में कश्मीर के हालात सुधरने और बिगड़ने का एक सिलसिला सा कायम रहा है। इस सिलसिले को समाप्त कर घाटी के हालात सामान्य बनाने और वहां स्थाई शांति लाने की आवश्यकता है। चूंकि हाल में खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वह कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं इसलिए वहां के हालात सुधरने को लेकर लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है। इस अपेक्षा की पूर्ति समय की मांग भी है।

इससे इन्कार नहीं कि कश्मीर समस्या जटिल है और उसका रातोंरात समाधान नहीं हो सकता, लेकिन इसका भी कोई औचित्य नहीं कि वहां अराजकता और अस्थिरता का दौर जारी रहे। यह दौर बीते करीब तीन दशकों से जारी है। इस पर विराम लगाने के लिए आतंक और अलगाव के समर्थकों पर दबाव बनाना जरूरी हो गया था। यह सर्वथा उचित है कि इस क्रम में घाटी में असर रखने वाले उन तत्वों को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है जिन्होंने दबे-छिपे ढंग से अलगाववाद को हवा देने का काम किया है। शायद ऐसे तत्वों की ओर संकेत करते हुए ही रक्षा मंत्री ने यह कहा कि यहां कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर का विकास हो। अलगाव को पोषण देने वाले इन तत्वों को सचमुच नाकाम करने का समय आ गया है। जैसे यह एक सच्चाई है कि कश्मीर के बिगड़े हालात के लिए वहां के राजनीतिक दल भी एक बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं वैसे ही यह भी कि पाकिस्तान ने घाटी को तबाह करने का काम किया है। यह अच्छा हुआ कि रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत हो या न हो, कश्मीर मसले का समाधान होगा। हालांकि इन दिनों पाकिस्तान पस्त है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि वह कश्मीर समस्या के समाधान में सहयोग करने के लिए तैयार होगा। इन स्थितियों में मोदी सरकार को अपने स्तर पर ही कश्मीर को शांत करने की कोशिश करनी होगी। अगर घाटी में अमन-चैन कायम हो गया तो एक तो पाकिस्तान के लिए वहां हस्तक्षेप करना कठिन हो जाएगा और दूसरे भारत को अपनी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा समय एवं संसाधन मिल जाएंगे। चूंकि कश्मीर में शांति की स्थापना भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया को भी एक नया माहौल प्रदान करने वाली साबित होगी इसलिए इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए।

हाईकोर्ट की फटकार

पश्चिम बंगाल में आए दिन पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की विभिन्न अदालतों में किरकिरी होती रहती है। इस बार उत्तर 24 परगना जिले की बनगांव नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान को अनुचित करार देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगरपालिका के चेयरमैन शंकर आढ्य को फटकार लगाई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने शंकर आढ्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नगरपालिका में बहुमत न होने के बाद भी आप कुर्सी पकड़े हुए हैं? आप इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हैं? न्यायाधीश ने कहा कि नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने विश्वास मत को खारिज कर दिया। बनगांव नगरपालिका के भाजपा पार्षदों ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वर्तमान चेयरमैन शंकर आढ्य को हटाने की मांग की थी। इस मामले पर अदालत ने सुनवाई करते हुए अपनी राय रखी। भाजपा पार्षदों ने दावा किया है कि 22 सदस्यीय बनगांव नगरपालिका के अधिकांश पार्षदों ने चेयरमैन के प्रति अविश्वास जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही भाजपा पार्षदों को पश्चिम बंगाल नगरपालिका प्रक्रिया व आचरण अधिनियम 1995 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन निर्धारित तिथि व समय पर भाजपा पार्षदों को पुलिस ने नगरपालिका कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया और बाद में बताया गया कि निर्धारित समय पर भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति में तृणमूल पार्षदों ने बैठक कर 11 में से 10 मतों के बहुमत से मतदान प्रक्रिया संपन्न कर शंकर आढ्य को बतौर चेयरमैन चुना है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर 24 परगना जिले की हालीशहर नगरपालिका का है, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश समाप्ति चट्टोपाध्याय ने 23 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। आखिर इस तरह का कार्य क्यों हो रहा है, जहां बार-बार हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति न बने, यह प्रशासन को देखना चाहिए।

कारगर कूटनीति का एक और उदाहरण

संजय गुप्त

यह आशंका निर्मूल है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की अनदेखी कर सकता है, क्योंकि वह इस समय चौतरफा दबाव से घिरा है

अवधेश राजपूत

करीब दो वर्ष पहले जब भारत सरकार पाकिस्तान में बंदी बनाए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लेकर गया था तब कई लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यह कदम उलटा पड़ सकता है। ऐसे लोगों का मत था कि इस मसले को पाकिस्तान से बातचीत के जरिये सुलझाना बेहतर रहता। मोदी सरकार की कूटनीतिक सोच यह थी कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ले जाकर ही पाकिस्तान को घेरा जा सकता है और कुलभूषण को राहत दिलाई जा सकती है। आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुलभूषण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला पाकिस्तान पर दबाव बनाने और साथ ही उसे शर्मसार करने वाला है। मार्च 2016 में कुलभूषण को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें आनन-फानन सैन्य अदालत के हवाले कर दिया था। अप्रैल 2017 में इस अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इसकी भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में घोषणा की कि भारत कुलभूषण को बचाने के हरसंभव उपाय करेगा। अगले ही महीने भारत कुलभूषण की सजा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया। तब इस न्यायालय ने अंतरिम फैसला देते हुए कुलभूषण को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी। अब उसने अपने अंतिम फैसले में भी फांसी की सजा रोकने और साथ ही उसकी समीक्षा करने और उस पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। यह सामान्य बात नहीं कि 16 जजों की पीठ में से 15 ने एकमत से यह फैसला दिया। इन न्यायाधीशों ने कुलभूषण को राजनयिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कुलभूषण को भारतीय नागरिक मानते हुए पाकिस्तान को वियना संधि के उल्लंघन का दोषी करार दिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण की गिरफ्तारी की सूचना देने में देर की और फिर उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से भी इन्कार किया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि उसमें चीन के न्यायाधीश की सहमति शामिल है। ध्यान रहे कि चीन पाकिस्तान के संरक्षक देश के रूप में उभरा है। भले ही पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को अपनी जीत बता रहा हो, लेकिन यह तय है कि उस पर दबाव बढ़ा है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों की भी इस पर निगाह रहेगी कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर ढंग से अमल करता है या नहीं? इस फैसले का अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कुलभूषण जैसे मामले रह-रह कर सामने आते रहते हैं। कई देश दूसरे देशों के नागरिकों को गिरफ्त में लेकर उन्हें वैसे ही जासूस करार देते हैं जैसे पाकिस्तान ने कुलभूषण को करार दिया। अब ऐसे सभी नागरिकों को कानूनी मदद मिलने का रास्ता और मजबूत हो गया है। पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से अगवा कर उन्हें बलूचिस्तान में तोड़फोड़ का जिम्मेदार बताने का काम इसीलिए किया था ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि उसके इस इलाके में अशांति और अस्थिरता के लिए उसकी अपनी दमनकारी नीतियां नहीं, बल्कि भारत का हस्तक्षेप जिम्मेदार है। पाकिस्तान की पोल तभी खुल गई थी जब उसने यह प्रचारित करने की कोशिश की थी कि कुलभूषण ने बलूचिस्तान में अमुक-अमुक हमलों को अंजाम दिया है। यह इसलिए हास्यास्पद था, क्योंकि एक अकेला आदमी यह सब नहीं कर सकता। उसकी पोल तब भी खुली थी जब उसने कुलभूषण का वीडियो जारी किया था। करीब दो दर्जन कट वाले इस वीडियो में कुलभूषण का इकबालिया बयान था। इस वीडियो ने यही साबित किया कि पाकिस्तान ने झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण के इसी तथाकथित इकबालिया बयान के आधार पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव की पैरवी करते हुए यह साबित किया था कि पाकिस्तान ने किस तरह न्याय के नाम पर मजाक किया है। उन्होंने मेहनताने के तौर पर केवल एक रुपया लिया, जबकि पाकिस्तान ने अपने वकील को बतौर फीस करोड़ों रुपये चुकाए। यह जो आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की अनदेखी कर सकता है वह इसलिए निर्मूल है, क्योंकि वह इस समय चौतरफा दबाव से भी घिरा है और गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की अनदेखी कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निशाने पर आने का जोखिम नहीं ले सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि वह आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम न उठाने के कारण पहले से ही अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ के निशाने पर है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण की सजा रद करने की भारत की मांग को नहीं माना, फिर भी यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुलभूषण को तुरंत छोड़ने की मांग की। पाक पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। वह दबाव में आता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि उसकी ओर से यह कहा गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप जाधव को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने के कदम उठा रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हुई हो। इसके पहले उसे तब शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी जब सुरक्षा परिषद ने पाक में पल रहे जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद उसे तब भी शर्मिंदा होना पड़ा था जब एफएटीएफ ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उसे काली सूची में डाला जा सकता है। बार-बार फजीहत के बावजूद भारत के प्रति पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आने की संभावना कम ही है। शायद इसीलिए मोदी सरकार भी उसके प्रति अपना रुख-रवैया नहीं बदल रही है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के साथ भारत ने उसके खिलाफ जो रवैया अपनाया उससे वह अपने को मुश्किलों से घिरा पा रहा है।

बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने यह शोर मचाने की बहुत कोशिश की कि उसकी सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है, लेकिन दुनिया ने भारत का ही पक्ष लिया। भारत ने यह स्पष्ट कर उसकी मुश्किल बढ़ाने का ही काम किया है कि उससे तब तक बातचीत संभव नहीं जब तक वह आतंक के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाता। पाक को ऐसा ही संकेत तब दिया गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करने का फैसला लिया और फिर शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से औपचारिक मुलाकात करने से इन्कार किया। शायद इसी चौतरफा दबाव के कारण पाकिस्तान का कश्मीर राग धीमा पड़ा है। अब जब यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के प्रति अपने सख्त रवैये में बदलाव नहीं लाने वाली तब फिर विपक्षी दलों के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वे पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सरकार का साथ दें। निरंतर दबाव ही पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को छोड़ने के लिए विवश कर सकता है।

response@jagran.com

मानसून सरीखा राजनीतिक माहौल

हास्य-व्यंग्य

अहो मित्र, कैसा समय आया है। अहो मित्र, चहुंओर चुनावोपरांत लोकतंत्र की धज जगमगा रही है। नवनिर्वाचित नेतागण संस्कारी दुल्हन की भांति जालिम जनता की भेदती निगाहों से दूर पहुंच गए हैं। महीने महीने ईंट-कुत्ते का बैर निभाने के बाद विपक्षी दलों के लोग एक दूसरे को प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव भरी दृष्टि से तक रहे हैं। पक्ष-विपक्ष का भेद मिटा जा रहा है। जो विपक्ष मे थे, पक्ष में आ रहे हैं। जो नहीं आए हैं, वे आने वाले हैं। अंतरात्मा का कॉल सेंटर फुल कैपेसिटी पर चल रहा है। बेंच से उठ-उठकर अंतरात्मा विपक्षी नेताओं को फोन लगा रही है और भावुक नेता दिनबदिन भाव विह्वल होकर विपक्ष से पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। हर खुदरा व्यापारी का स्वप्न थोक व्यापारी बनना होता है। कर्नाटक में भाजपा खुदरा व्यापार के प्रयास में तत्कालीन थोक विक्रेता कांग्रेस से मुंह की खाने के बाद अब होलसेल मार्केट में उतर आई है। चुनाव के बाद जब भाजपा वाले एक पाव भिंडी छांट रहे थे, कांग्रेस टोकरी उठा कर चल दी थी। समझदार वही है जो इतिहास से सीख ले, सो इस बार सौदा थोक में होगा, गोवा में भी और कर्नाटक में भी। इसे मॉल में मिलने वाली उस पेशकश की तरह देखा जा सकता है जहां एक किलो के साथ दो सौ ग्राम सामान मुफ्त में दिया जाता है।

तीसरी सदी में रोम में देवी एथेना के मंदिर से उठा पार्किंग विवाद, मीर बकी के दौर से गुजरता हुआ नए भारत की पुरानी दिल्ली तक पहुंच गया है। जिस प्रकार फुटबॉल के खेल में हाफटाइम के बाद टीमें पाले बदल लेती हैं, धर्मनिरपेक्ष अतिवादी पाले में आ बैठे हैं और अतिवादी धर्मनिरपेक्षता वाले पाले में खेल रहे हैं। टीमों के पाला

साकेत सूर्येश

कौन कहां है और जहां है वहीं रहेगा, यह पता नहीं चलता। कौन कहां से कहां जाएगा, यह भी पता नहीं चल रहा है

बदलने से दर्शक दीर्घा में निराशा का माहौल है। राजनीति एक अध्यात्मिक प्रश्न हो गई है जहां जो है वह नहीं है, जो नहीं है वही सही है। अभिव्यक्ति की आजादी के प्रश्न पर भाजपा कांग्रेस के पाले में खड़ी है और अध्यक्षहीन कांग्रेस कहीं नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि नेहरू आज होते तो भाजपा में भर्ती हो जाते और श्यामा प्रसाद मुखर्जी झोला उठाकर देशाटन पर चले जाते। केवल कांग्रेस के अध्यक्ष का सवाल ही सतह पर नहीं है। सवाल यह भी सतह पर है कि कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष कितनी लंबी बहस करा सकते हैं? इंतजार शक्ति परीक्षण का नहीं, इसका हो रहा है कि बहस कितनी लंबी खींची जा सकती है। देखना है कि कोई रिकार्ड बनता है या नहीं?

मानसून आ चुका है, लेकिन कहीं-कहीं नहीं भी आया है। देश के कई हिस्सों में आसमान पर बादल मंडराते भी हैं तो वे चुनावी वादों की तरह खोखले ही साबित हो रहे हैं। ऐसे दौर में मौसम विभाग नई-नई तारीखें बता रहा है। देश के कुछ हिस्सों में आसमान भले ही बारिश से सूखा है, लेकिन कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। जो दे रहा है उसे न देने को मनाया जा रहा है, जो नहीं दे रहा है उसे त्यागपत्र देने को उकसाया जा रहा है। जिन्हें त्यागपत्र देना चाहिए उनसे मांगा नहीं जा रहा है। खबर निकालने वाले कांग्रेस से निराश होकर शादी के फूफाजी, हमने तो पहले ही कहा था, वाली मुद्रा में हाथ बांधे खड़े हैं। चुनाव बाद से टोपी पहनाने-उतारने का नैरेटिव बार-बार फिसलता जा रहा है। इससे खबरनवीसों में हताशा का माहौल है। इस माहौल में भी कुछ खुशी के मौके तलाशते रहते हैं। वे हर सुबह या दूसरी सुबह इसके या उसके उत्पीड़न की खबर सोशल मीडिया पर डालते हैं। ऐसी तथाकथित खबरें शाम तक झूठी खबर निकल जाती हैं। सच्ची खबरों के अभाव मे बुद्धिजीवियों का यह वर्ग स्वतः खबरें बनाने को विवश है। जिस समाज में बुद्धिजीवी आक्रोशित न हो, कुर्ता-पाजामा न पहने और सिगरेट-शराब न पी सके, यह अपने आप में समाज के लिए स्वयं ही शर्म का विषय है।

कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल मानसून में मुंबई की सड़क सा हो गया है। कौन कहां है और जहां है वहीं रहेगा, कुछ पता नहीं चलता। कौन कहां जाएगा, यह भी पता नहीं चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश और बाढ़ में यह पता नहीं चलता कि कहां नाला है, कहां सड़क? कब तक कौन किधर चलेगा और कब किसी नाले में निकल लेगा, पता ही नहीं लगता। सब गड्ड-मड्ड हो गया है।

response@jagran.com

ऊर्जा

नकारात्मकता

जीवन में नकारात्मकता समस्त शक्ति को क्षीण कर देती है और उत्साह का दमन कर हमें कमजोर बनाती है। नकारात्मक विचार हमें पतन की ओर धकेलते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है तो हमारे भीतर संशय का भाव उत्पन्न हो जाता है। यही संशय अनिर्णय का निमित्त बनकर हमारे कदमों की गति में बाधक बनता है। इससे जीवन में उन्नति प्रभावित होती है। नकारात्मकता चरित्र को विरोधाभासी बना देती है। कोई भी व्यक्ति हम पर सहज रूप से विश्वास नहीं करता और हम स्वयं दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। परस्पर विश्वास की कमी के कारण व्यक्ति समाज से कटने लगता है। समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना करना मुश्किल है। एकाकी व्यक्ति सफलता से विमुख हो जाता है। नकारात्मकता अंधकार है। जो हमारे विवेक को भ्रम में डाल देती है। भ्रमित मस्तिष्क किसी भी प्रकार के निर्णय में सफल नहीं हो सकता है। निर्णय न लेने की क्षमता हमें पंगु बना देती है। मानसिक रुग्णता भयावह है। यह वैचारिक कपाट बंद कर देती है। विचारशून्यता मृत्यु के समान है। नकारात्मकता सुख का हरण कर लेती है। यह केवल हमें क्षोभ प्रदान करती है, विसंगति प्रदान करती है। हमारी व्यावहारिक नकारात्मकता हमारे पतन को आमंत्रित करती है। जिस कारण हम जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाते।

शास्त्रों में नकारात्मकता को मनुष्य का घोर शत्रु बताया गया है। ऐसे में इसे स्वयं के पास फटकने भी न दें। इससे दूरी बनाएं रखें। सकारात्मकता को आमंत्रित कर उसे यथासंभव पोषित करें। यह न केवल आपको प्रसन्नता देगी, अपितु आपके समग्र व्यक्तित्व को आकर्षण प्रदान करेगी। जीवन को श्रेष्ठता एवं सार्थकता प्रदान करने के लिए नकारात्मक भाव का वध करना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। नकारात्मक भावों की परछाई भी हमें बहुत क्षति पहुंचा सकती है। स्वयं को दीनता से बचाने के लिए नकारात्मकता से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। सकारात्मक भाव हमें ऊर्जावान बनाता है। हमारी विवेकशीलता को शक्ति देता है। नकारात्मकता के साथ हमारी सामाजिक स्वीकार्यता भी संभव नहीं है। ऐसे में नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना ही श्रेयस्कर माना जाता है।

ललित शौर्य

तथ्य-कथ्य

वाहन उद्योग की चाल

जून 2019 में वाहनों की बिक्री

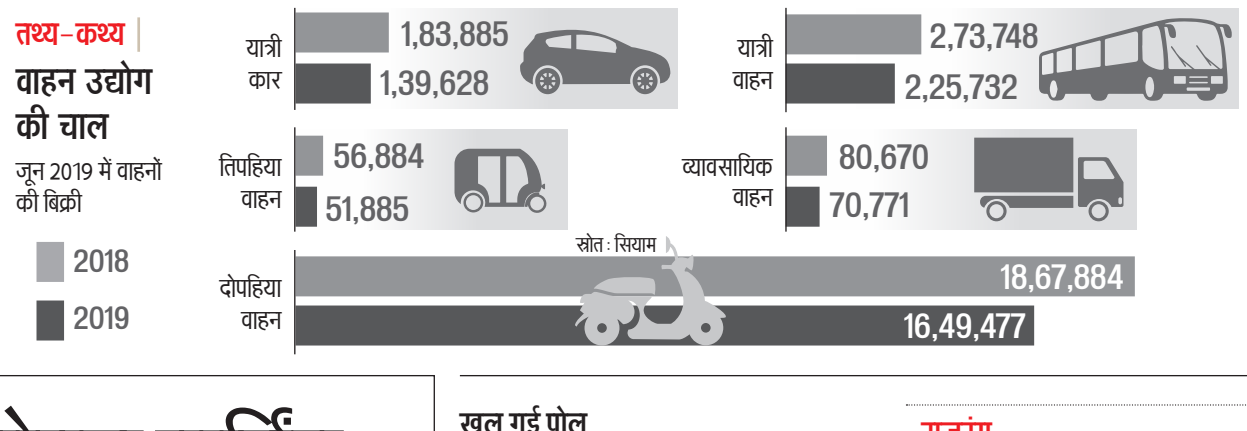

नए पेड़ों से थमेगी ग्लोबल वार्मिंग

मुकुल व्यास

वैज्ञानिकों ने जंगलों, खेतों को घटाकर हिसाब लगाया कि धरती पर कितने अतिरिक्त जंगल लगाए जा सकते हैं

यदि ग्लोबल वार्मिंग का मौजूदा रुझान जारी रहा तो वर्ष 2030 तक दुनिया के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन पेड़ इस जलवायु संकट से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक नए विश्लेषण से पता चला है कि करीब एक हेक्टेयर अतिरिक्त जंगल लगाने से वायुमंडल में वर्ष 1800 के बाद छोड़े गए 300 अरब टन कार्बन के दो-तिहाई हिस्से को हटाया जा सकता है। ये पेड़ 200 अरब टन कार्बन को सोखकर उसका भंडारण कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अरब हेक्टेयर जंगल लगाकर 2050 तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी पर अतिरिक्त पेड़ लगाने की कितनी गुंजाइश है और पेड़ कहां लगाए जा सकते हैं। उन्होंने वर्तमान जंगलों के उपग्रहों से लिए गए चित्रों का विश्लेषण किया। इसके पश्चात शोधकर्ताओं ने पृथ्वी को मिट्टी और जलवायु की 10 विशेषताओं के आधार पर श्रेणीबद्ध किया। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जो विभिन्न जंगलों के लिए अधिक या कम उपयुक्त हैं। उन्होंने वर्तमान जंगलों, खेतों और शहरों की जमीनों को घटाकर हिसाब लगाया कि धरती पर कितने अतिरिक्त जंगल लगाए जा सकते हैं।

इससे पता चला कि ऐसे क्षेत्रों में जहां मनुष्य की गतिविधि बहुत कम है और जिनका उपयोग शहरी या कृषि भूमि के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है, वहां 1.7 से 1.8 अरब हेक्टेयर जमीन में जंगल उगाए जा सकते हैं। इससे 90 करोड़ हेक्टेयर जंगलों का इजाफा होगा। इस बीच एक अन्य अध्ययन में यह भी कहा गया है कि खेतों की जमीनों और शहरी क्षेत्रों में भी अतिरिक्त पेड़ उगाने की काफी गुंजाइश है। अतिरिक्त जंगल सिर्फ कार्बन को ही नहीं हटाएंगे, इनसे और भी कई फायदे होंगे। इनसे जैव-विविधता में वृद्धि होगी, पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और भू-क्षरण में कमी आएगी। विभिन्न क्षेत्रों में जंगलों की बहाली की लागत अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इन वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार नए जंगल को उगाने का खर्च 300 अरब डॉलर बैठेगा। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में लगने वाले जंगल कितना कार्बन सोखेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के कुछ ऐसे उपकरण तैनात हैं जो पृथ्वी के वन आवरण पर नजर रखते हैं। इनमें ग्लोबल इकोसिस्टम डायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह उपकरण जंगलों के 3डी नक्शे तैयार करने के लिए लेजर का प्रयोग करेगा। इन आंकड़ों से जंगलों द्वारा कार्बन के भंडारण का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक प्रो. साइमन लेविस ने नए अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जंगलों द्वारा 200 अरब टन कार्बन के भंडारण का अनुमान बहुत अधिक है। नए जंगल कुछ मात्रा में कार्बन उत्सर्जन से निपटने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन जलवायु को स्थिर करने का एकमात्र तरीका यह है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि खनिज तेलों से होने वाले उत्सर्जन में भारी कटौती करनी पड़ेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

खुल गई पोल

इन दिनों भाजपा सांसदों के होश उड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हाल में भाजपा सांसदों को इसका प्रत्यक्ष अहसास तब हुआ जब नाश्ते पर उनसे मुलाकात के दौरान मोदी ने पूछ लिया कि पिछले दिनों लोकसभा की कार्यवाही कितने बजे तक चली। केवल तीन सांसद ही सही-सही बता सके और यही तीन सांसद रात 12 बजे तक लोकसभा में मौजूद थे। जो मौजूद नहीं थे उनकी पोल खुल चुकी थी।

हिंदी की खातिर

हिंदी भाषा की शुद्धता को लेकर अकेले हिंदी भाषा से जुड़े विद्वान व लेखक ही चिंतित नहीं है, बल्कि ऐसी संजीदगी माननीयों में भी देखने को मिल रही है। राज्यसभा में हाल ही में एक रोचक वाकया हुआ। एक सदस्य ने मंत्रालय की ओर से अपने सवाल के हिंदी में दिए गए जवाब में शब्दों की अशुद्धि पर सवाल खड़ा कर दिया। साथ ही मंत्री से जानना चाहा कि उन्हें दिए गए जवाब में जिस 'अनुमत्य' शब्द का इस्तेमाल किया है, ऐसा हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। वाकया इसलिए ज्यादा रोचक हो गया, क्योंकि सवाल हिंदी में पीएचडी की डिग्री रखने वाले मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से ही किया गया था। पांडेय ने भी तत्काल भरोसा दिया कि आगे से ऐसी गड़बड़ी न हो इसका पूरा ख्याल रखेंगे।

दल बदलने पर भी जीता दिल

सफेद लिबास भले ही राजनीति की पहचान बन गया हो, मगर वास्तविकता में रंग बदलना सियासत की फितरत है। बहरहाल सियासी लिबास का रंग बदलने के बाद भी मौजूदा दौर में पुराने रिश्तों के शिष्टाचार को नहीं भूलने का वाकया हो तो बरबस यह ध्यान खिंचता है। बीते दिनों सपा की राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए नीरज शेखर के ऐसे ही व्यवहार को संसद के गलियारे में देखा गया। भाजपा में शामिल होने के बाद संसद भवन पहुंचे नीरज अपनी नई पार्टी का पटका गले में लटकाए भाजपा नेताओं से गले मिलकर बधाई ले रहे थे। इसी दरम्यान सपा सांसदों के साथ कुछ दूरी पर खड़े रामगोपाल यादव पर उनकी नजर पड़ी तो नीरज गले से पटका निकाल तत्काल उनकी ओर बढ़े। फिर रामगोपाल के पांव छूकर अपनी नई राजनीतिक पारी के लिए उनका आशीर्वाद लिया। पार्टी बदलने के बाद भी शिष्टाचार नहीं भूलने के इस वाकये को देख कई दूसरे सांसदों ने उनकी प्रशंसा भी की।

राज्यमंत्रियों को बंधी आस

भाजपा में संगठन का कामकाज देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लगातार नए लोगों को आगे बढ़ाने और जिम्मेदारी देकर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जाने गए। पार्टी में दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा करने में उनका खास योगदान रहा। सरकार में आए तो यहां भी उनकी यह कोशिश बरकरार है। दरअसल सरकार में राज्यमंत्री का ओहदा पाने वाले अक्सर निराश होते हैं। उनकी बड़ी परेशानी यह होती है कि बड़े मंत्री उनके लिए कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। उन्हें छोटे-छोटे काम ही दिए जाते हैं जिनके सहारे वे कभी सुर्खियों में नहीं आ पाते, लेकिन शाह इसके उलट कर रहे हैं। संसद में वह लगातार अपने दो राज्यमंत्रियों नित्यानंद राय और जी किशन रेड्डी को भरपूर अवसर दे रहे हैं। आलम यह है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी ये दोनों मंत्री ही जवाब दे रहे हैं। हालांकि इस बीच शाह भी लगातार मौजूद होते हैं ताकि कोई बड़ा सवाल खड़ा हो तो वह खुद उसे संभाल पाएं। शाह के ऐसे रवैये से अब दूसरे राज्यमंत्रियों में भी आशा जगी है कि शायद शाह की देखादेखी दूसरे कैबिनेट मंत्री भी उदार होंगे।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।